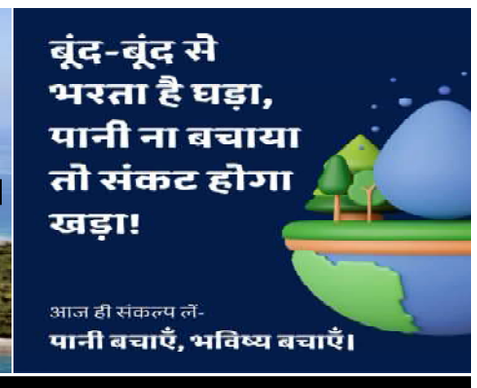


अण्डमान निकोबार
द्वीप समाचार



रजि.न.34300/80 संख्या 293 श्री विजय पुरम, सोमवार, 02 नवम्बर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

अनेकता में एकता है भारत की पहचान : डॉ. दिनेश शर्मा

अण्डमान बनेगा देश की समृद्धि और सुरक्षा का द्वार

जनजातीय समूह के मन में है विकास की नई उमंग

अण्डमान में होते हैं लघु भारत के दर्शन

लोगों के बीच में एकता और देश के प्रति समर्पण है प्रगति का आधार

अण्डमान ने किया वीबी राम जी योजना में सबसे अधिक रोज़गार सृजन



















श्री विजयपुरम, 1 नवम्बर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है तथा वही इस देश की आत्मा है। अण्डमान आने वाले समय में देश की सुरक्षा और सम्पन्नता का द्वार बनने जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया के पटल पर अमिट पहचान बनाएगा।

माननीय उप राज्यपाल ने द्वीपसमूह के स्थापना दिवस पर टैगोर कॉलेज, श्री विजयपुरम, अण्डमान निकोबार में आयोजित भव्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि आज देश के 10 राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु आदि केन्द्र शासित तथा अन्य प्रदेशों का स्थापना दिवस है जिसे देश के लोग मिलकर मना रहे हैं। देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एकता की अनुभूति कर रहा है। त्योहार के समय में जनजातीय समूह के मन में विकास की नई उमंग दिख रही है। लोग एक बार फिर से मिलकर विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। जिस प्रकार से सुरो के संगम से शानदार संगीत बनता है, उसी प्रकार अण्डमान में अलग–अलग धर्म के पर्वो को सम–समय पर साथ में मनाने से जीवन में नई उमंग पैदा होती है।

समारोह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस को एक साथ मनाकर देश में एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्ष्यद्वीप, पुदुचेरी के मूल निवासियों ने जो अण्डमान में आकर बसे हैं उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ की संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि भारत अलग–अलग संस्कृतियों का समूह है। भारत माता को गंगा माता, गऊ माता और धरती माता का त्रिकोण बताते हुए कहा कि देश तीन प्रकार की संस्कृतियों का समागम है। अण्डमान में भारत की सभी संस्कृतियों का वास है जिससे यहां पर विविधता में एकता तथा लघु भारत के दर्शन होते हैं।

डॉ. शर्मा ने कहा कि भारत को आक्रान्ताओं ने लूटा जरूर पर वे यहाँ की संस्कृति, साहित्य और परम्परा को नष्ट नहीं कर सके। जो भारत को लूटने आए थे वे बरबाद हो गए है। ब्रिटेन जिसने भारत पर राज किया वह कमज़ोर हुआ है और भारत सात प्रतिशत से भी अधिक की जीडीपी के साथ दुनिया की बडी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। भारत की इस तरक्की का कारण निवासियों के बीच में एकता, समन्वय और देश के प्रति समर्पण का भाव है।

माननीय माननीय उप राज्यपाल महोदय का कहना था कि अण्डमान काला पानी नहीं बल्कि अब अमृत वाणी और अमृत पानी के लिए जाना जाएगा। यही इसकी सांस्कृतिक पहचान भी है। देश को आगे लेकर जाने का बड़ा अभियान चल रहा है। सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिली यातनाओं को याद करते हुए कहा कि देश को आज़ादी उनके त्याग का परिणाम है। देश की स्वतंत्रता में तमाम ज्ञात–अज्ञात सेनानियों का योगदान है। देश से अंग्रेज़ तो चले गए पर मानसिकता यही रह गई। उसका दुष्प्रभाव देश में दिखाई देता है। देश के लोगों को अपनी भाषा एवं हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, यही उनकी प्रगति का आधार है। ये भाषा का नहीं बल्कि मानसिकता का विरोध है। जब तक पाश्चात्य संस्कृति के प्रति लगाव रहेगा तब तक देश की प्रगति बाधित होती रहेगी। हर व्यक्ति को अपने देश एवं सांस्कृतिक विरासत पर गौरव होना चाहिए। स्थापना दिवस अपने गौरव व परम्पराओं को याद करने का दिन है।

माननीय उप राज्यपाल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल को गौरवशाली बताते हुए कहा कि इस समय में ही देश ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाये हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का यज्ञ आरम्भ हो चुका है। इस कड़ी में अण्डमान ने बडी उपलब्धि हासिल करते हुए वीबी–जी राम जी योजना के तहत रोज़गार सृजन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। द्वीपसमूह के दो स्थान यूनेस्कों ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। आज का भारत श्रेष्ठ भारत हो तथा दुनिया में इसका नाम हो इसके लिए काम किया जाए। अब अण्डमान देश की मुख्यधारा में शामिल हो चुका है। देश में द्वीपसमूह के प्रति आकर्षण



बढ रहा है। आने वाले समय में द्वीपसमूह को सभी सुविधाओं से युक्त बनाने का काम तेजी से होगा जिससे यहां की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव आए।

डॉ. शर्मा ने कहा कि आज का भारत नक्सलमुक्त है, जिसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नया भारत है जो डरता भी नहीं और डराता भी नहीं है। आज पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। पहले के समय में पाकिस्तानी हमले का जवाब शान्ति के प्रतीक कबूतर को उडाकर दिया जाता है।

इस अवसर पर माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय, सचिव, कला संस्कृति श्रीमती ज्योति कुमारी, उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान श्रीमती पूर्वा गर्ग, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण अण्डमान श्रीमती श्वेता के. सुगथन, इतिहासकार डॉ. रशीदा इक़बाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री नीरज भारती, श्री सतनाम सिंह, श्री प्रवेश रंजन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की उपस्थिति में अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह की तटीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित





श्री विजयपुरम, 1 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटीय सुरक्षा तथा इससे जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर, 2026 को अण्डमान तथा निकोबार पुलिस मुख्यालय, श्री विजयपुरम के सम्मेलन कक्ष में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की संयुक्त अध्यक्षता राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी) वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त) और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक ने की।

इस संगोष्ठी में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा द्वीपसमूह की तटीय एवं समुद्री सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में वर्तमान समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, परिचालन तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ डीआईजीपी (कानून एवं व्यवस्था)/सीआईडी के स्वागत संबोधन से हुआ। इसके पश्चात एसपी (पीएमएफ)/एसएमएससी, एएनआई द्वारा 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तटीय पुलिसिंग' विषय पर प्रस्तुति दी गई। इसमें वर्तमान तटीय सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की परिचालन क्षमताओं तथा द्वीपसमूह की विस्तृत समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की समुद्री बल की भूमिका को विस्तार से रेखांकित किया गया। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की रणनीतिक सुरक्षा एवं संवेदनशीलताएं' विषय पर प्रस्तुति दी। इसमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस द्वीपसमूह से जुड़े प्रमुख सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।

भारतीय तटरक्षक बल ने 'सीमापार अवैध मछली पकड़ने एवं समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं, मत्स्य विभाग ने 'तटीय सुरक्षा में मछुआरे : सुरक्षा व्यवस्था की आंख और कान' विषय पर प्रस्तुति देते हुए तटीय निगरानी और खुफिया सूचनाएं एकत्र करने में मछुआरा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद तटीय सुरक्षा से जुड़े हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, विभिन्न एजेंसियों के बीच परिचालन समन्वय तथा मौजूदा चुनौतियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अण्डमान–निकोबार पुलिस के निरीक्षक विजय कुमार को प्रतिष्ठित 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक–2026' के लिए चुना गया

श्री विजयपुरम, 1 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के लिए गौरव का विषय है कि श्री विजयपुरम स्थित अबर्डीन पुलिस थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) निरीक्षक विजय कुमार को प्रतिष्ठित 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक–2026' के लिए चयनित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की स्वीकृति से प्रदान किए जाने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य, कर्तव्यनिष्ठा एवं विशिष्ट सेवाओं को मान्यता दी जाती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस पदक की स्थापना देशभर की पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों में उच्च पेशेवर मानकों, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है।

निरीक्षक विजय कुमार को यह सम्मान अनुसंधान श्रेणी में उनके उत्कृष्ट योगदान, निरंतर समर्पण और विवेचना संबंधी दक्षता के लिए प्रदान किया गया है। उनकी यह उपलब्धि अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की उच्च कार्यक्षमता, पेशेवर प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट पुलिसिंग का परिचायक है।

उनका चयन न केवल अण्डमान तथा निकोबार पुलिस बल, बल्कि समूचे द्वीपसमूह के नागरिकों के लिए भी गर्व और प्रसन्नता का विषय है। उनकी यह उपलब्धि पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित



करेगी। दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अण्डमान तथा निकोबार पुलिस 'निर्भय, निपुण, निष्पक्ष' के आदर्श वाक्य के साथ कार्य करते हुए द्वीपसमूह में कानून–व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निरीक्षक विजय कुमार की इस उपलब्धि को अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं और समर्पित कार्यशैली की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

कैंपबेल बे में आंचलिक स्तरीय विज्ञान, गणित एवं कला प्रदर्शनी 'इनोविजन 3.0' का आयोजन

कैंपबेल बे, 1 नवंबर।

पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैंपबेल बे में कल आंचलिक स्तरीय विज्ञान, गणित एवं कला–कौशल प्रदर्शनी 'इनोविजन 3.0' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निकोबार डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) श्री रवि कांत ने किया।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री रवि कांत ने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक जिज्ञासा, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा एवं नवाचार की क्षमता को विकसित करने तथा शिक्षा के माध्यम से नए अवसर तलाशने का संदेश दिया। इस अवसर पर कैंपबेल बे के प्रमुख श्री ई. एस. राजेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विज्ञान एवं गणित संबंधी मॉडल, कला–तियों और रचनात्मक प्रदर्शनों का अवलोकन किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में उनकी कल्पनाशीलता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार के प्रति रुचि देखने को मिली।



कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब का भी उद्घाटन किया गया। इस प्रयोगशाला की स्थापना विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मक सोच और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रयोग करके सीखने तथा अपने नए विचारों को वास्तविक स्वरूप देने के अवसर प्राप्त होंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 'इनोविजन 3.0' प्रदर्शनी ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया।

राष्ट्रीय एकता दिवस–2026 : अण्डमान–निकोबार पुलिस ने 'बड़ा खाना' के माध्यम से मनाया एकता, सौहार्द और टीम भावना का उत्सव







श्री विजयपुरम, 1 नवंबर।

राष्ट्रीय एकता दिवस–2026 के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर, 2026 की शाम अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा पुलिस लाइन्स, श्री विजयपुरम में 'बड़ा खाना' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का हिस्सा था। कार्यक्रम में पुलिस की विभिन्न इकाइयों एवं शाखाओं के अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर एकता, आपसी सौहार्द, भाईचारे और सामूहिक गौरव का वातावरण देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान एक आकर्षक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति, राष्ट्रीय एकीकरण और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के साथ–साथ एकता, पारस्परिक सम्मान और आपसी सहयोग जैसे मूल्यों का संदेश दिया गया, जो एक सशक्त एवं संगठित पुलिस बल की आधारशिला हैं। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जवानों से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को अपने कार्यों में सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और समर्पण की सराहना करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए टीम भावना, आपसी विश्वास तथा बेहतर समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया। 'बड़ा खाना' कार्यक्रम में स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसकी उपस्थित लोगों ने काफी सराहना की। उत्कृष्ट आयोजन व्यवस्था, आत्मीय आतिथ्य सत्कार और विशेष रूप से तैयार किए गए व्यंजनों ने समारोह की रौनक को और बढ़ा दिया तथा इस शाम को यादगार बना दिया। पुलिस अधीक्षक (एपीयू) द्वारा प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'बड़ा खाना' कार्यक्रम ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों एवं शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों और जवानों को नियमित ड्यूटी से इतर एक साथ मिलने, आपसी संवाद स्थापित करने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया तथा पुलिस बल की साझा पहचान एवं सामूहिक मूल्यों को भी सुदृढ़ किया।

मंगलूटान स्कूल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजयपुरम, 1 नवंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा 29 अक्टूबर को दक्षिण अण्डमान के मंगलूटान स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मंगलूटान पशु चिकित्सालय के माध्यम से संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंगलूटान पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने विद्यार्थियों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सूअरों को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत संक्रामक विषाणुजनित रोग है। विद्यार्थियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती और मानव स्वास्थ्य के लिए इसका कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है, लेकिन इससे सूअरों के स्वास्थ्य तथा सूअर पालन पर निर्भर परिवारों की आजीविका को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

जागरूकता सत्र में विद्यार्थियों को सूअरों में इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों की पहचान करने के बारे में बताया गया। इनमें तेज बुखार, भूख न लगना, कमज़ोरी, त्वचा के रंग में बदलाव तथा अचानक मृत्यु जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके अलावा, बीमारी के फैलने के विभिन्न माध्यमों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि संक्रमित सूअरों के संपर्क में आने तथा दूषित जूते–चप्पलों, उपकरणों और सूअर के मांस से बने उत्पादों के आवागमन के माध्यम से भी संक्रमण फैल सकता है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे बीमार या मृत सूअरों के संपर्क में न आएं, किसी संदिग्ध मामले की जानकारी तत्काल अपने अभिभावकों या शिक्षकों को दें तथा इसकी सूचना शीघ्र पशु चिकित्सा विभाग तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। यह जागरूकता कार्यक्रम मंगलूटान पशु चिकित्सालय द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोकथाम और जन–जागरूकता के लिए चलाए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा था। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे बीमारी से बचाव संबंधी सही जानकारी अपने परिवारों और स्थानीय समुदायों तक भी पहुंचाएं, ताकि समय रहते आवश्यक सावधानियां अपनाई जा सकें।

पश्चिम एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप–2026 में अण्डमान–निकोबार के पांच खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

श्री विजयपुरम, 1 नवंबर।

गुजरात के अहमदाबाद में 21 से 30 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित पश्चिम एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप–2026 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पांच युवा शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के कुल 595 युवा शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में ओपन एवं बालिका वर्ग के अंतर्गत छह आयु श्रेणियों में स्टैंडर्ड, रैपिड और ब्लिट्ज स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। द्वीपसमूह के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में इन तीनों प्रारूपों में प्रतिस्पर्धा की।

खिलाड़ियों का प्रदर्शन

1. स्टैंडर्ड शतरंज (9 राउंड)
साव जिन्सन सैमुअल (अंडर–10)–9 में से 5 अंक
एम. रित्विक (अंडर–8)–9 में से 4.5 अंक
जे. एस. विराट (अंडर–16)–9 में से 4 अंक
एस. ईशान (अंडर–10)–9 में से 3.5 अंक
टी. ईसांथ (अंडर–8)–9 में से 2.5 अंक
2. रैपिड शतरंज (7 राउंड)
साव जिन्सन सैमुअल (अंडर–10)–7 में से 4.5 अंक
एस. ईशान (अंडर–10)–7 में से 3.5 अंक
एम. रित्विक (अंडर–8)–7 में से 3 अंक
जे. एस. विराट (अंडर–14)–7 में से 2.5 अंक
टी. ईसांथ (अंडर–8)–7 में से 2 अंक
3. ब्लिट्ज शतरंज (7 राउंड)
साव जिन्सन सैमुअल (अंडर–10)–7 में से 5 अंक
एस. ईशान (अंडर–10)–7 में से 3 अंक



एम. रित्विक (अंडर–8)–7 में से 3 अंक
जे. एस. विराट (अंडर–14)–7 में से 2.5 अंक
टी. ईसांथ (अंडर–8)–7 में से 2 अंक

अण्डमान तथा निकोबार शतरंज संघ (एएनसीए) ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पांच खिलाड़ियों के प्रयासों, समर्पण और उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी से द्वीपसमूह के युवा खिलाड़ियों को विभिन्न देशों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपने खेल कौशल को निखारने का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

श्री विजयपुरम, 1 नवंबर।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2026 को दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण (लाइव स्क्रीनिंग) किया गया। इस पहल में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ–साथ आम नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति, आपसी सद्भाव और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रोत्साहित करना था। साथ ही, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान से लोगों को अवगत कराना भी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रहा। सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के माध्यम से देशी रियासतों के एकीकरण तथा भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी पहलों के माध्यम से दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस, पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय एवं सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ–साथ 'विविधता में एकता' की भावना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पुलिस का उद्देश्य नागरिकों को शांति, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

सात हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'डिजी यात्रा' का ट्रायल शुरू

2027 में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए ट्रायल के दौरान यात्रियों से ली जाएँगी प्रतिक्रियाएं

भारत के सात हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'डिजी यात्रा' के ट्रायल शुरू किये गए हैं। यह देश के विमानन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक और कदम है। नवंबर से दिसंबर 2026 तक चलने वाले इन ट्रायल के दौरान, ई–पासपोर्ट रखने वाले पात्र भारतीय नागरिक, एयर इंडिया और इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करते समय, हवाई अड्डों पर तय किए गए टचपॉइंट्स पर शडिजी यात्राश का उपयोग कर सकेंगे। ये ट्रायल दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, मुंबई, चेन्नई और अमृतसर हवाई अड्डों पर किए जा रहे हैं। पात्र यात्री टर्मिनल प्रवेश बिंदुओं, सुरक्षा होल्ड क्षेत्रों (एसएचए) और बोर्डिंग गेटों पर, जहाँ भी आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध है, इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। ट्रायल अवधि के दौरान मिलने वाले फीडबैक के आधार पर 2027 में इसके व्यापक विस्तार की योजना तैयार की जाएगी।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, पात्र भारतीय नागरिकों को डिजी यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ई–पासपोर्ट–आधारित सत्यापन योग्य जानकारी (वीसी) देनी होगी। इस प्रक्रिया में ई–पासपोर्ट के मशीन के जरिये पठनीय ज़ोन (एमआरजेड) को स्कैन करना, एक उपयुक्त स्मार्टफोन के शनियर फील्ड कम्यूनिकेशनश (एनएफसी) फीचर का उपयोग करके पासपोर्ट में लगी चिप को पढ़ना, एक सेल्फी लेना और विवरणों को सत्यापित करना शामिल है। यह जानकारी यात्री के डिवाइस पर उनके डिजी यात्रा वॉलेट में सुरक्षित हो जाती है और इसका उपयोग ट्रायल के लिए सक्षम किए गए हवाई अड्डे के टचपॉइंट्स पर किया जा सकता है।

इस सुविधा का उद्देश्य मौजूदा यात्रा प्रक्रियाओं की जगह लेना नहीं, बल्कि उनमें सहयोग करना है। यात्रियों को अपने यात्रा दस्तावेज़ साथ रखने होंगे और एयरलाइन द्वारा ज़रूरी दस्तावेज़ों की जाँच, आव्रजन प्रक्रियाओं और यात्रा से जुड़ी अन्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

भारत के विमानन नेटवर्क में डिजी यात्रा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इस प्लेटफॉर्म के 26.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं और इसने घरेलू एयरलाइनों को सेवा प्रदान करते हुए 39 घरेलू हवाई अड्डों पर 110 मिलियन से अधिक यात्राओं को सुगम बनाया है। 2027 तक 25 और घरेलू हवाई अड्डों को इसके दायरे में लाने की योजना है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के शडिजिटल इंडियाश और उड़ान को आसान बनाने के .ष्टिकोण के अनुरूप, हवाई अड्डे के कामकाज को बेहतर बनाने और हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया; वायुसेना के भविष्य के लिए 'वायु' को मार्गदर्शक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम ने 1 नवंबर को भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, नई दिल्ली स्थित वायुसेना स्टेशन पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

एयर चीफ मार्शल दीक्षित को एक परीक्षण पायलट और योग्य उड़ान प्रशिक्षक के रूप में 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर कार्य किया है। इनमें मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ में प्रमुखों की स्टाफ समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीआईएससी), केंद्रीय वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ और वायुसेना के उप प्रमुख जैसे पद शामिल हैं।

वायुसेना प्रमुख ने अपने पहले संबोधन में भारतीय वायुसेना के लिए अपना दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने 'वायु' नाम से एक मार्गदर्शक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसके चार प्रमुख स्तंभ भारतीय वायुसेना की भविष्य की दिशा तय करेंगे।

सतर्कता, विजय एवं तत्परताः सभी वायुसेना इकाइयों में परिचालन तैयारियों का उच्चतम स्तर बनाए रखना और युद्ध क्षमता को निर्धारित मानकों के अनुरूप बहाल करना।

आत्मनिर्भरताः विमान, संवेदक, हथियार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य परिचालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा निरंतर युद्ध क्षमता बनाए रखना है।



युक्तिः युद्ध सिद्धांतों, प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रक्रियाओं में दूरदर्शिता व नवाचार को अपनाना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमान एवं नियंत्रण प्रणाली, ड्रोन रोधी क्षमताएं, परिचालन में लचीलापन व उभरते हुए युद्ध क्षेत्र शामिल हैं।

प्रयासों में एकजुटताः राष्ट्रीय दृष्टिकोण 'जय' यानी संयुक्तता, आत्मनिर्भरता एवं नवाचार के अनुरूप थलसेना, नौसेना और विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय व संयुक्त कार्यक्षमता को और मजबूत करना।

'वायु' दृष्टिकोण के माध्यम से वायुसेना प्रमुख ने ऐसी भारतीय वायुसेना के निर्माण की स्पष्ट दिशा तय की है, जो हर परिस्थिति में परिचालन के लिए तैयार, तकनीकी रूप से उन्नत, आत्मनिर्भर और बेहतर समन्वय से युक्त हो। यह वायुसेना अपनी सशक्त वायु शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और संभावित संघर्षों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने भूटान में 108 स्तूपों की स्थापना समारोह में भाग लिया

केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 01 नवंबर 2026 को भूटान के श्गेलेफू माइंडफुलनेस सिटीश में 108 स्तूपों की स्थापना और प्राण–प्रतिष्ठा समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इस समारोह में भूटान के महामहिम राजा भी उपस्थित थे। 108 स्तूपों के इस कार्यक्रम में श्री रिजिजू की उपस्थिति, भारत और भूटान के लोगों के बीच साझा आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों और गहरी मित्रता को दर्शाती है। 108 स्तूपों की यह परियोजना भूटान के महामहिम राजा की परिकल्पना थी, जिन्होंने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन भी किया। असम की सीमा के पास श्गेलेफू माइंडफुलनेस सिटीश में, श्आई (माउ)श नदी के किनारे 11.7 किलोमीटर के दायरे में, हज़ारों स्वयंसेवकों ने एक ही दिन में 108 स्तूप खड़े कर दिए। इनमें से प्रत्येक स्तूप 15 मीटर ऊँचा है और हर एक के बीच 108 मीटर की दूरी है। इस परियोजना का उद्देश्य श्गेलेफू माइंडफुलनेस सिटीश को वज्रयान बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है और साथ ही इसके माध्यम से भूटानी लोगों के मूल्यों और संस्ति को भी दर्शाना है।

भूटान के महामहिम राजा, भूटान के प्रधानमंत्री और श्री रिजिजू ने स्तूप संख्या 76 पर प्रार्थना की, जिसे भूटान के राजा द्वारा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया गया है। श्री रिजिजू ने इस परियोजना के हिस्से के रूप में एक स्तूप समर्पित करने की इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से भूटान के महामहिम राजा के प्रति आभार व्यक्त किया।

31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक अपनी भूटान यात्रा के दौरान, श्री रिजिजू ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से मुलाकात की और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोबगे से भी बातचीत की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच की विशेष मित्रता और विकास सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, निवेश, कनेक्टिविटी तथा सांस्तिक संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के सकारात्मक रुझान की सराहना की। श्री रिजिजू ने श्गेलेफू माइंडफुलनेस सिटीश जैसी दूरदर्शी परियोजना के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह परियोजना भूटान के साथ–साथ भारत के पड़ोसी क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारतीय नौसेना के पोत त्रिशूल का ग्रीस की सूडा खाड़ी में प्रवास

भारतीय नौसेना का पोत त्रिशूल भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के तहत 31 अक्टूबर, 2026 को ग्रीस की सूडा खाड़ी पहुंच गया है। पोत का चालक दल बंदरगाह पर अपने ठहराव के दौरान भारतीय नौसेना व यूनानी नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें एथेंस में यूनानी नौसेना और भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें, पेशेवर बातचीत, एक–दूसरे के जहाजों का दौरा और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, चालक दल को नेवल सपोर्ट एक्टिविटी (एनएसए) सूडा बे और नाटो मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर (एनएमआईओटीसी) की सुविधाओं से भी परिचित कराया जाएगा।

भारतीय नौसेना के पोत त्रिशूल का चालक दल सूडा बे युद्ध स्मारक कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित



करेगा। बंदरगाह पर इसके ठहराव के दौरान यह पोत आगंतुकों के लिए भी खुला रहेगा। यह यात्रा समुद्री सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के साथ–साथ भारतीय नौसेना तथा यूनान की नौसेना के बीच पेशेवर संबंधों को भी सशक्त करेगी।

एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल, एवीएसएम, वीएम ने पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ के रूप में कार्यभार संभाला

एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल, एवीएसएम, वीएम ने 1 नवंबर 2026 को भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एयर मार्शल देसवाल 14 जून 1989 को भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में लड़ाकू विमान पायलट के रूप में कमीशन हुए थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों को उड़ाने का 3,200 घंटे से अधिक का अनुभव है। वे आक्रमणकारी विमानों के संचालन और वायु रक्षा के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा, वह योग्य पायलट आक्रमण प्रशिक्षक भी हैं। एयर मार्शल देसवालने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है।

एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल ने अपने सेवाकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण परिचालन और स्टाफ संबंधी पदों पर कार्य किया है। इनमें दो वायुसेना अड्डों के एयर ऑफिसर कमांडिंग और एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन के कमान अधिकारी का पद शामिल है। वे पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में वायुसेना अताशे के रूप में भी तैनात रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक



(हथियार प्रणाली) के रूप में सेवाएं दी हैं। पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ का कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल देसवाल दक्षिण–पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी (एसएएसओ) के पद पर कार्यरत थे।

उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए एयर मार्शल देसवाल को अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।

त्योहारी सीजन में सोने–चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, चांदी 1.86 लाख रूपए के करीब

त्योहारी सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। हते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं पर दबाव देखने को मिला। अमेरिका में महंगाई के अपेक्षा से अधिक रहने, फेडरल रिजर्व के दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावनाओं और ऊंची बॉन्ड यील्ड के चलते एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर में 3,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। इसका फायदा फिलहाल धनतेरस और दिवाली से पहले खरीदारी की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना करीब 0.28 प्रतिशत गिरकर 4,020 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी 1.20 प्रतिशत टूटकर 51.750 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

अमेरिकी कोर पीसीई महंगाई सितंबर में 0.3 प्रतिशत बढ़ी, जबकि वार्षिक दर 3.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके साथ ही तीसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की 3.4 प्रतिशत वृद्धि ने यह संकेत दिया है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। बाजार अब दिसंबर में फेड की ओर से दर बढ़ोतरी की संभावना 80 प्रतिशत से अधिक मान रहा है, जिससे गैर–ब्याज देने वाली संपत्तियों जैसे सोने पर दबाव बना हुआ है।

वहीं, वैश्विक कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। घरेलू बाजार में सोना गिरकर 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.86 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती दिखाई दी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना अपने पिछले बंद भाव 1,42,596 से



800 रुपए से ज्यादा या 0.59 प्रतिशत टूटकर 1,41,753 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी में और बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह अपने पिछले बंद भाव 1,89,453 रुपए से 3,730 रुपए या 1.96 प्रतिशत गिरकर 1,85,723 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर आ गया।

चांदी अब अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से आधे से भी कम भाव पर आ गई है। बता दें कि इस वर्ष जनवरी के आखिरी सप्ताह में सिल्वर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख रुपए का ऐतिहासिक स्तर पार किया था और 4,20,048 रुपए का हाई लेवल टच किया था, लेकिन इसके बाद इसमें लगातार गिरावट आई, और अब चांदी अपने उच्चतम स्तर से आधे से बी कम कीमत पर मिल रही है। यही वजह है कि लंबी अवधि के निवेशकों और त्योहारी खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा स्तर आकर्षक हो सकते हैं। हालांकि अल्पकाल में फेडरल रिजर्व की नीति, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की दिशा तय करेंगी। (इनपुट–एजेंसी)

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का 67वाँ स्थापना दिवस

जैव विविधता निगरानी और वन्यजीव संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने आज सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक श्संडे बर्ड वॉक / एनजेडपीश के 19वें संस्करण का आयोजन किया। यह वॉक समर्पित स्वयंसेवकों के सहयोग से, पक्षी विज्ञानी डॉ. परितोष अहमद के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पक्षी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और जैव विविधता में रुचि रखने वाले नागरिकों सहित कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान, प्रतिभागियों ने 46 पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया और निर्दिष्ट क्षेत्र में 500 से अधिक व्यक्तिगत पक्षियों को देखा। टिप्पणियों ने क्षेत्र–स्तरीय जैव विविधता दस्तावेज़ीकरण में योगदान दिया और प्रतिभागियों को नागरिक विज्ञान में संलग्न होने का व्यावहारिक अवसर प्रदान किया। विशेषज्ञ ने पक्षी पारिस्थितिकी, व्यवहार और संरक्षण में अंतर्दृष्टि साझा की, प्राकृतिक कीट नियंत्रण सहित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की भूमिका और पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में उनके मूल्य पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, निदेशक (एनजेडपी) ने इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति की सैर उस क्षेत्र को पहचानने के कौशल को मजबूत करती है, पारिस्थितिक संबंधों और खादस्य जाल की समझ को गहरा करती है, जैव विविधता दस्तावेज़ीकरण का समर्थन करती है और वन्यजीव संरक्षण की स्थायी सराहना को बढ़ावा देती है।

पीएमजीएसवाई–IV के तहत मिजोरम में नई सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी

पीएमजीएसवाई-IV (बैच–1, वित्त वर्ष 2026–27) के तहत 45 सड़क कार्यों (509.54 कि.मी) जिनका मूल्य रु. 710.40 करोड़ है, का प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जिससे 48 बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा । सड़क संपर्क मिलने से इन बसावटों को आवश्यक सुविधाएँ जैसे स्कूल, अस्पताल एवं ग्रामीण मण्डियों तक पहुँच मिलेगी जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी । यह सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को भी पूरा करने में सहायक होगी ।

उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त, आज तक, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य मे रु. 3,412 करोड़ की राशि वाले 367 सड़क कार्यों (4,935 कि.मी.) एवं 07 पुलों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

ईपीएफओ की 74 साल की यात्रा श्रमिकों के विश्वास, सेवा और प्रतिबद्धता पर आधारित है: डॉ. मनसुख मांडविया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आज नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया, जो एक सांविधिक भविष्य निधि संगठन से भारत के अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में से एक बनने की उसकी यात्रा को दर्शाता है। साथ ही, इसमें तकनीक–आधारित सेवा वितरण, शासन में करुणा और लाखों श्रमिकों व पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया।



इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने की। इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री चंद्र भूषण कुमार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य, श्रमिक, नियोक्ता और अन्य हितधारक भी उपस्थित थे।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपनी 74 साल की यात्रा के दौरान ईपीएफओ घ्यदेश के कार्यबल के लिए एक विश्वसनीय संस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने उल्लेख किया कि संगठन में व्यक्त किया गया विश्वास 8 करोड़ से अधिक सदस्यों के अंशदान से जमा हुए 32 लाख करोड़ रुपये के कोष में परिलक्षित होता है, जो ईपीएफओ घ्यके कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हुआ है।

डॉ. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की हर चिंता और शिकायत का समाधान करुणा व सहानुभूति के साथ किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक श्रमिक को वह सम्मान और गरिमा दी जानी चाहिए जिसके वे राष्ट्र–निर्माता के रूप में हकदार हैं। सीआईटीईएस 2.01 जैसे तकनीकी बदलावों के पीछे किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने सभी अधिकारियों से अंतिम छोर के श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताए गए श्पंच प्रणश से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। डॉ. मांडविया ने कहा, "सेवा ही हमारा संस्कार हैं।" उन्होंने सभी को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ईपीएफओ घ्यके 75वें वर्ष के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक–केंद्रित नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करें तथा बदलते समय के अनुरूप प्रक्रियाओं को अपनाएं, उन्हें सुदृढ़ बनाएं और उन्हें विकसित करें। उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं तथा ईपीएफओ के सभी घ्यअधिकारियों, सदस्यों और लाभार्थियों के जीवन में सफलता व समृद्धि की कामना की।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कहा कि ईपीएफओ घ्यने राष्ट्र की सेवा में सात दशकों से अधिक समय के दौरान भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे की नींव रखी है और उसे मजबूत किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल तैयार हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक सुरक्षा और श्रम सुधार न केवल संगठित क्षेत्र तक, बल्कि असंगठित क्षेत्र के अंतिम छोर के श्रमिकों तक भी पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे किस तरह हासिल किया जा सकता है। यह देखते हुए कि आज का दिन इस बात पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि हम अब तक कितनी दूर आ चुके हैं और हमें अभी कितना आगे जाना है, उन्होंने कहा कि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज के डिजिटल युग में आम आदमी की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए इसमें लगातार बदलाव और विकास की आवश्यकता है। उन्होंने इन सुधारों से जुड़े अधिकारियों से अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के सामूहिक प्रयासों के बीच, लाभार्थियों के लिए सुविधाओं तक पहुंच और जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अपने संबोधन में, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने ईपीएफओ घ्यकी 74 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। 1952 में अपनी स्थापना के समय लिए गए संकल्प से लेकर आज एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका तक, ईपीएफओ घ्यलगभग 8 करोड़ अंशदायी सदस्यों और 85 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। साथ ही लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के रिटायरमेंट कॉर्पस को भी सुरक्षित रख रहा है। उन्होंने देश भर के अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान को सराहा, जिनके प्रयासों से सेवाएं लगातार मिलती रहीं, जबकि इस दौरान संगठन ने कई महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक बदलावों को अपनाया है। ईपीएफओ घ्यको और अधिक सुलभ, विश्वसनीय व मानवीय बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि संस्था के प्रति विश्वास तब बनता है जब हर दावे का सेटलमेंट होता है, हर पेंशन समय पर प्रदान की जाती है और कठिन समय में परिवारों को मदद मिलती है। उन्होंने दोहराया कि ईपीएफओ घ्यकी सफलता का असली पैमाना यही है कि इसके सदस्य और पेंशनभोगी कितना भरोसा व सुरक्षा महसूस करते हैं।

सीआईटीईएस 2.01 के माध्यम से ईपीएफओ के तकनीकी बदलाव के प्रभाव को भी प्रदर्शित किया गया। दावों के निपटारे में एक महत्वपूर्ण सुधार रेखांकित किया गया, जहां अक्टूबर 2026 में औसत निपटारे की अवधि घटकर 2.57 दिन हो गई। यह सुधार भविष्य निधि की बचत को सदस्यों के लिए अधिक तीव्र और सुगम बनाने के संगठन के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

ईपीएफ सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए मुख्य पहल और उनके लाभ

1. व्हाट्सएप के माध्यम से ईपीएफओ घ्यसेवाएं
ईपीएफ सदस्य ईपीएफओ घ्यकी सत्यापित व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से अपना पीएफ बैलेंस, पिछले पांच लेन–देन और पासबुक की जानकारी देख सकेंगे। साथ ही, उन्हें पीएमवीबीआरवाई से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता भी मिलेगी। इससे रोज़मर्रा की सेवाएं एक जाने–पहचाने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी और ईपीएफओ घ्यकार्यालय जाने की ज़रूरत कम हो जाएगी।

2. पात्र निष्क्रिय ईपीएफ खातों के ऑटोमेटिक सेटलमेंट की शुरुआत
जिन सदस्यों के आधार–सत्यापित ईपीएफ खाते निष्क्रिय हैं और जिनमें 1,000 रुपये तक की राशि जमा है, उन्हें अलग से दावे (क्लेम) दायर करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ घ्यनिर्धारित पहचान और बैंक खाता सत्यापन के बाद ऑटोमेटिक सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिससे पात्र लाभार्थियों को उनकी देय राशि मिल सकेगी। इससे कुल 5 करोड़ रुपये की राशि के लगभग एक लाख खातों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रकाशन जारी किए गए और उत्कृष्ट को मान्यता दी गई

इस अवसर पर सात प्रकाशन जारी किए गए, जो ज्ञान सृजन, संस्थागत सीख, कानूनी जागरूकता और संवेदनशील शासन के प्रति ईपीएफओ घ्यकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं:

1. ईपीएफओ स्टेट प्रोफाइल 2026: इसमें ईपीएफओ की भौगोलिक उपस्थिति, राज्यवार कवरेज, सदस्यता, प्रतिष्ठान, दावे और पेंशनभोगी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

2. न्यायिक निर्णयों का संकलन 2026: सामाजिक सुरक्षा कानूनों से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक घोषणाओं का संकलन जो सुविचारित और सुसंगत निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

3. केंद्र निधि – हिंदी पत्रिका 2026–27: ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारियों के साहित्यिक एवं रचनात्मक योगदान को प्रदर्शित करती है तथा हिंदी को बढ़ावा देती है।

4. काम के दायरे से परे, सामान्य गतिविधियों के अलावा: यह ईपीएफओ कर्मियों की पेशेवर जिम्मेदारियों के अलावा उनकी अन्य विविध प्रतिभाओं और उपलब्धियों का सम्मान करता है।

5. शासन की पुनर्कल्पना: उत्कृष्टता हेतु विमर्श (आरजीडीई): यह पीडीयूएनएएसएस द्वारा शुरू की गई संवाद श्रृंखला से मिली जानकारियों को संकलित करता है, जो नैतिक नेतृत्व, संवेदनशील शासन और संस्थागत परिवर्तन पर केंद्रित है।

6. शासन–विधि में करुणा: इसमें 62 क्षेत्रीय कार्यालयों के 83 वास्तविक अध्ययन शामिल हैं, जो सदस्यों की शिकायतों के समाधान में सहानुभूति और अभिनव तरीकों को दर्शाते हैं।

7. द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल सिक्योरिटी – वॉल्यूम 1, 2026: इसमें सामाजिक सुरक्षा, श्रम बाजारों, डिजिटल परिवर्तन और पेंशन प्रशासन के मौजूदा विषयों पर ईपीएफओ अधिकारियों के शोध लेख प्रस्तुत किए गए हैं।

भविष्य निधि पुरस्कार 2026 क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों, तथा व्यक्तिगत अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में क्षेत्रीय और जिला–स्तरीय प्रदर्शन, शिकायतों का प्रबंधन, पेंशन सेवाएं, मृत्यु दावा निपटान, श्प्रयासश और पीएमवीबीआरवाई का कार्यान्वयन, तकनीकी नवाचार, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, स्वच्छता, छूट प्राप्त प्रतिष्ठान और खेल–कूद जैसे क्षेत्रों में किए गए बेहतरीन कार्यों को शामिल किया गया। ये पुरस्कार सेवा प्रदायगी को मजबूत करने और संस्थागत उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में ईपीएफओ कर्मचारियों के समर्पण, नवाचार और प्रतिबद्धता को मान्यता देते हैं।

74वें स्थापना दिवस पर दिए गए संबोधन से एक साझा दृष्टिकोण उभर कर सामने आया: ईपीएफओ घ्यमें होने वाले बदलावों का अंतिम परिणाम हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए बेहतर सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास के रूप में दिखना चाहिए। जैसे–जैसे यह संगठन आगे बढ़ेगा, इसका प्रयास होगा कि तकनीकी प्रगति को मानवीय संवेदना के साथ, व्यापक सामाजिक सुरक्षा को भरोसेमंद सेवा के साथ, और संस्थागत दक्षता को शासन में करुणा के साथ जोड़ा जाए।

ईपीएफओ की यात्रा केवल एक संस्थागत विकास की कहानी भर नहीं है; बल्कि यह एक निरंतर प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी कर्मचारी की वर्षों की मेहनत का फल उसे और उसके परिवार को सुरक्षा, सम्मान व मानसिक शांति के रूप में मिले।

"गाँवों की जल–सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्षा की हर बूँद का संरक्षण आवश्यक है" – श्री दिलीप कुमार, सचिव, भूमि संसाधन विभाग





भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने डब्ल्यूडीसी–पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत पुणे जिले के खेड़ के गांवों में जलागम विकास कार्यों की समीक्षा की

श्री दिलीप कुमार, सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 अक्टूबर, 2026 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (डब्ल्यूडीसी–पीएमकेएसवाई 2.0) के जलागम विकास घटक के तहत किए जा रहे जलागम विकास कार्यों की समीक्षा की। इस योजना के तहत जलागम विकास के प्रमुख उद्देश्यों में मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी उपाय करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

कार्यों का निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों से बातचीत करते हुए श्री दिलीप कुमार ने कहा, "जल हमारे भविष्य का आधार है। **गाँवों की जल–सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्षा की हर बूँद का संरक्षण किया जाना चाहिए।**"

उन्होंने ग्रामीणों से जलागम विकास योजना के तहत निर्मित जल संचयन संरचनाओं के नियमित रखरखाव और मरम्मत की सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया, जिससे ये परिसंपत्तियाँ अगले 20 वर्षों तक कार्यशील बनी रहें। उन्होंने हिवरे बाजार की तर्ज पर खेड़ परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांवों को जल–सुरक्षित और आत्मनिर्भर समुदायों में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करने का भी आह्वान किया।

इस दौरे में भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) श्री नितिन खड़े; महाराष्ट्र सरकार के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर और वसुंधरा जलागम विकास एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अश्विनी जगताप ने भाग लिया।

सचिव महोदय ने ऊँचाई वाले क्षेत्रों से घाटी की ओर (रिज–टू–वैली) दृष्टिकोण अपनाकर विकसित जलागम संरचनाओं का निरीक्षण किया। इनमें सतत समोच्च खाइयाँ (सीसीटी), मिट्टी के नाला बाँध, सीमेंट नाला बाँध, कोल्हापुरी प्रकार के बंधारे और जल भंडारण के लिए तालाब शामिल थे। उन्होंने वर्षा जल के अपवाह को कम करने, भूजल पुनर्भरण बढ़ाने और कृषि के लिए जल की उपलब्धता में सुधार करने में इन संरचनाओं की प्रभावशीलता, भूजल स्तर में हुए बदलावों और लाभार्थियों को प्राप्त लाभों की समीक्षा की।

सचिव महोदय ने योजना के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए खेत तालाबों, बागवानी पौधरोपण और कृषि उपकरणों के साथ–साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए लाभों की भी समीक्षा की।

ग्रामीणों ने बताया कि खेड़ परियोजना के अंतर्गत 11 गांवों में किए गए जलागम विकास कार्यों से भूजल स्तर में सुधार हुआ है। इससे किसानों को प्रतिवर्ष दो से तीन फसलें उगाने में मदद मिली है, जिससे कृषि आय और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सूखे जैसी परिस्थितियों के बावजूद, खेत तालाबों में संचित जल और सीमेंट नाला बाँधों तथा सीसीटी संरचनाओं से जुड़े कुओं के जल स्तर में सुधार से खड़ी फसलों की सिंचाई में मदद मिली है।

29 अक्टूबर, 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने पुणे स्थित यशदा में महाराष्ट्र सरकार के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के सचिव के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने डब्ल्यूडीसी–पीएमकेएसवाई योजना की स्थिति तथा इसकी वित्तीय और भौतिक प्रगति की भी समीक्षा की।

श्री दिलीप कुमार ने अधिकारियों को महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। अल नीनो की परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने राज्य के 304 सूखाग्रस्त तालुकों में से योजना के अंतर्गत शामिल 76 तालुकों में कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। सूखे के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जलागम विकास कार्य महत्त्वपूर्ण हैं। प्राथमिकता वाले कार्यों में अंतःस्रवण टैंक, भंडारण तालाब, भंडारण बाँध और कोल्हापुरी प्रकार के बंधारे शामिल हैं, जिनसे वर्षा जल का भंडारण बढ़ने, गांवों में जल की उपलब्धता सुदृढ़ होने, फसलों को सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराने और सूखे जैसी परिस्थितियों के प्रति कृषि की संवेदनशीलता कम होने की अपेक्षा है। बैठक में निर्धारित समय–सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, केंद्र–राज्य समन्वय को सुदृढ़ करने और उपलब्ध निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इस दौरे से यह बात रेखांकित हुई कि सूखे के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने में जलागम विकास कार्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही, विकसित भारत के निर्माण के लिए जल–सुरक्षित गांवों के निर्माण में जल संरक्षण संरचनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव और सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को भी बल मिला।

भारत के 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश की जरूरत : एसोचैम



भारत को अपने 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जलवायु निवेश, अनुकूलन वित्त (अडैप्टेशन फाइनेंस), टेक्नोलॉजी सहयोग और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जानकारी तुर्किए में होने वाली कॉप31 क्लाइमेंट समिट से पहले इंडस्ट्री चैम्बर्स की ओर से दी गई।

इंडस्ट्री चैम्बर्स एसोचैम ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की बढ़ोतरी के साथ, जुलाई 2026 तक भारत की गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 300.5 गीगावाट तक पहुंच गई है।

बयान के अनुसार, भारत ने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही अपनी कुल बिजली क्षमता में गैर–जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक कर ली है।

एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने कहा, "देश ने यह साबित कर दिया है कि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था स्वच्छ ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपना सकती है। भारत ने तय समय से पांच साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा गैर–जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है।" उन्होंने आगे कहा कि कॉप31 में अमल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें उद्योग जगत की मुख्य भूमिका हो।

मिंडा ने कहा कि भारत के 2030 के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। साथ ही, बैटरी स्टोरेज की मांग 2027 तक 37 गीगावाट घंटा से बढ़कर 2031–32 तक 236 गीगावाट घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि स्थापित क्षमता को भरोसेमंद बिजली में बदलने के लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्टोरेज की व्यवस्था करना और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक स्वच्छ ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। बयान में कहा गया है कि एसोचैम प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और जलवायु–कार्य से जुड़े संबंधित समूहों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस रिपोर्ट में जलवायु वित्त जुटाने, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को निवेश और उनके क्रियान्वयन में बदलने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए जाएंगे। (इनपुट–आईएएनएस)